companies to submit their detailed project reports to the Central Electricity Authority by March, 31,1997, if so, the reasons therefor;

(b) whether Government have also instructed the State Governments to press for competitive bidding for equipment procurement and construction contracts and if so, what is the basis for it;

(c) whether it is a fact that several State Governments had signed MOUs just before the deadline was announced in February last year; and

(d) if so, what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S VENUGOPALACHARI): (a) Yes, Sir. With a view to ensure expeditious setting up incremental power generation capacities and to weed out non-serious promoters of all the private sector power projects which have been granted 'in-principle' clearance of Central Electricity Authority (CEA), all the State Governments-State Electricity Boards have been directed to ensure that the promoters submit their detailed projects reports (DPRs) along with firm cost estimates by 31.3.1997 for obtaining the techno-economic clearance of CEA.

(b) Yes, Sir. The State Governments and the State Electricity Boards have been advised to go in for International Competitive Bidding (ICB) in the selection of their EPC contracts, to make the system of finalising costs of private power projects more transparent.

(c) Yes, Sir.

(d) It has been clarified by the Union Government that unless a clear Letter of Intent was Issued or MOU signed between the State Government/State Electricity Board and the concerned party on or before 18.2.1995. It will not be considered by CEA for techno-economic clearance.

गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में लक्ष्य

1798. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या ग्रामीण-क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अब तक राज्य-वार कितने गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) राज्य-वार कितने गांवों में स्थायी रूप से पेयजल उपलब्ध कराया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) 1996-97 के दौरान स्वच्छ पेयजल सुविधाओं की कवर वाली बसावटों/गांवों के लक्ष्यों और उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ख) और (ग) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996-97 में कवर की जाने वाली बसावटों/गांवों की संख्या	
		लक्ष्य	31.5.96 तक उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	3100	175
2.	अरूणाचल प्रदेश	150	25
3.	असम	1500	183
4.	बिहार	17621	235
5.	गोवा	54	3
6.	गुजरात	1200	73
7.	हरियाणा	1263	55
8.	हिमाचल प्रदेश	1172	202

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996-97 में कवर की जाने वाली बसावटों/गांवों की संख्या	
		लक्ष्य	31.5.96 तक उपलब्धि
9.*	जम्मू एवं कश्मीर	350	—
10.	कर्नाटक	10414	497
11.	केरल	1065	39
12.	मध्य प्रदेश	9000	1126
13.	महाराष्ट्र	6000	737
14.	मणिपुर	310	3
15.	मेघालय	530	0
16.	मिजोरम	203	2
17.*	नागालैण्ड	124	—
18.	उड़ीसा	6000	714
19.	पंजाब	684	13
20.	राजस्थान	5000	741
21.	सिक्किम	200	0
22.	तमिलनाडु	2500	28
23.	त्रिपुरा	795	32
24.*	उत्तर प्रदेश	12953	—
25.	पश्चिम बंगाल	4711	525
26.*	अंडमान व निकोबार द्वी॰ समू॰	15	—
27.*	दादरा व नगर हवेली	12	—
28.*	दमन व दीव	29	—
29.	दिल्ली	0	0
30.	लक्ष्यद्वीप	3	0
31.	पांडिचेरी	28	3
	कुल	86985	5411

विवरण-II

बसावटों की कवरेज की राज्यवार स्थिति

	कुल बसावटों की सं॰	1.4.96 तक की स्थिति		
		एन सी	पी सी	एफ सी
आंध्र प्रदेश	67684	0	17777	49907
अरुणाचल प्रदेश	2446	197	606	1643
असम	70669	11627	23726	35316
बिहार	205436	16085	10783	178568

	कुल बसावटों की सं०	1.4.96 तक की स्थिति		
		एन सी	पी सी	एफ सी
गोआ	405	50	41	314
गुजरात	30269	717	7974	21578
हरियाणा	6848	0	1680	4804
हिमाचल प्रदेश	43781	5086	12469	26226
जम्मू व कश्मीर	7763	845	3988	2930
कर्नाटक	56682	6045	8475	42162
केरल	9719	863	7382	1474
मध्य प्रदेश	127083	5724	19842	101517
महाराष्ट्र	77124	22	12762	64340
मणिपुर	2815	391	906	1518
मेघालय	7876	860	1874	5142
मिजोरम	919	12	190	717
नागालैंड	1304	354	787	163
उड़ीसा	74231	0	18376	55855
पंजाब	12797	5403	336	7058
राजस्थान	81773	11597	16725	53451
सिक्किम	1679	0	1033	646
तमिलनाडु	66615	366	38883	27366
त्रिपुरा	7412	242	2750	4420
उत्तर प्रदेश	274641	12360	97313	164968
पश्चिम बंगाल	80377	0	25537	54840
अ०नि० द्वीप समूह	504	11	53	440
दा० नगर हवेली	0	0	0	0
दमन व द्वीव	0	0	0	0
दिल्ली	200	0	62	138
लक्षद्वीप	11	0	4	7
पांडिचेरी	0	0	0	0
कुल	1318699	78857	332334	907508

एन सी: कवर न की गई

पी सी: आंशिक रूप से कवर

एफ सी: पूर्ण रूप से कवर

Monitoring of Funds Under JRY

1799. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the State-wise details of funds allocated under Jawahar Rojgar Yojana;

(b) whether Government have any monitoring mechanism to see that such